ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य

(रिट याचिका (सीआरएल) सं. 180/ 2006)

21 फरवरी 2017

[जगदीश सिंह खेहर मुख्य न्यायाधिपति डॉ. डी. वाई चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल न्यायाधिपतिगण]

जम्मू और कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997:

अवमानना की कार्यवाही- याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा आयोजित और याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रकाशित एक सामान्य अध्ययन- न्यायपालिका के कामकाज के संबंध में उसमें निर्देश- आरोप है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में 92% अधीनस्थ न्यायपालिका को भ्रष्ट माना जाता है- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन, जम्मू और कश्मीर ने याचिकाकर्ताओं सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, और उनके स्पष्टीकरण और न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किए- याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए नोटिस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दायर कीं कि चूंकि कार्यवाही न्यायालय की अवमानना अधिनियम और रणबीर दंड संहिता के यूएलएस

2 (डी) आरएलडब्ल्यू एसएस 499, 500/501 के तहत शुरू की गई थी, मजिस्ट्रेट के पास न तो अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार था और न ही इसके लिए उच्च न्यायालय निर्देश देने का अधिकार था। इसके बाद, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानती वारंट के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति चाहते हूये करते हुए आदेश पारित किया गया- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका- अभिनिर्धारित- न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आक्षेपित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था, जिसके तहत उसने याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चि करने पर विचार किया।- मजिस्ट्रेट को कानून के अनुरूप मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी- यदि न्यायालय यह समझ रही थी कि मामले को या तो न्यायालय अवमानना अधिनियम या 2/6 सहपठित धारा 499,500/501 रणबीर दंड संहिता के अंतर्गत आगे ले जाने की जरूरत है, न्यायालय को विधि के अनुरूप ऐसा करना चाहिए था- रणबीर दंड संहिता, संवत 1989- धाराये 2/6 सहपठित धारा 499, 500/501

धारा. 15- अधिनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध लगाए गए सामान्य आरोपों के लिए क्या किया जा सकता है-निर्धारित जब कई सामान्य अदालतों के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं, तथा किसी विशिष्ट न्यायाधीश या न्यायालय को लक्षित नहीं करते हैं, तब कोई भी न्यायालय या न्यायाधीश निर्देश कर सकते हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य

[जगदीश सिंह खेहर, मुख्य न्यायाधिपति]

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. यह कहना सही नहीं है कि जम्मू-कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 की धारा 15 के तहत एक निर्देश केवल उस विशिष्ट न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है, जिसकी अवमानना कथित तौर पर की गई थी, न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा। इस याचिका के अनुसार, अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश करना उचित नही होगा, जहां सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केवल इसलिए कि वर्तमान मामले में आरोप किसी विशिष्ट न्यायालय पर लक्षित नहीं थे, 1997 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। 1997 के अधिनियम की धारा 15(2) में प्रयोग किया गया शब्द "अधीनस्थ न्यायालय" एक ऐसी स्थिति पर विचार कर सकता है, जहां कथित अवमाननापूर्ण कार्रवाई एक से अधिक अदालतों, या बड़ी संख्या में अदालतों के विरुद्ध एक साथ लक्षित होती है। उस स्थिति में, ऐसी अदालतों में से कोई भी, जम्मू और कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश दे सकता है। जहां अवमाननापूर्ण कार्रवाई

सामान्य प्रकृति की है, और विशिष्ट न्यायाधीश या न्यायालय को लक्षित नही है तब, ऐसे न्यायाधीश या न्यायालय में से कोई भी, जो मानता है कि इसका लक्ष्य उसके लिए है, उसके अधिकार में होगा कि वह क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय को इसका निर्देश दे। और उसके बाद, यदि संज्ञान लेने और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है, तो यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आएगा। [पैरा 18] [675-बी, सी, ई-एच]

2.1 वर्तमान मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंगन जिस के पास दिनांक 24.8.2006 को पारित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र या प्राधिकार नहीं था, जिसके तहत, उसने गिरफ्तारी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं व अन्य की उपस्थिति को सुनिश्चित करने पर विचार किया। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं का यह मानना था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 4.5.2006 को शुरू की गई कार्यवाही गलत थी। याचिकाकर्ताओं से उनकी लिखित तर्कों के रूप में में प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, और जबकि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं की है, तब न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधि के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए था। और यदि यह न्यायालय की समझ थी, कि मामले को आगे ले जाने की जरूरत है, या तो न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 के तहत या रणबीर दंड संहिता की धारा 499, 500/501 के सहपठित धारा 2/6 के तहत न्यायालय को ऐसा करना चाहिए था. [पैरा 19] [676-ए-डी]

2.2 न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन के न्यायालय का प्रभार संभालने वाले न्यायिक अधिकारी को मूल कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.5.2006 के अग्रसरण में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें (या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से)। यदि याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो वह कानून के अनुरूप ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, जो वह उचित समझे। [पैरा 20] [676-ई-एफ]

3. यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रणबीर दंड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के तहत आगे बढ़ना चाहता है, तो न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199-बी के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई याचिका को उचित रूप से विचार में लेगा कि नोटिस लेगा। रणबीर दंड संहिता की धारा 499, 500/501 सहपठित धारा 2/6 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के लिए अधिकार नहीं है। [पैरा 21] [676- एच; 677-ए]

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार रिट याचिका: (आपराधिक) संख्या 180/2006

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

जयन्त भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोहित कुमार. सिंह (प्रशांत भूषण के लिए), अधिवक्तागण। याचिकाकर्ताओं कि और से।

एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, अधिवक्तागण। प्रत्यथिगण कि और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

जगदीश सिंह खेहर, मुख्य न्यायाधिपति:

हस्तगत रिट याचिका दो याचिकाकर्ताओं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के लिए इस न्यायालय के समक्ष आने का कारण सेंटर फॉर मीडिया स्टडी द्वारा संचालित और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित "गवर्नेंस में सुधार के लिए भारत में भ्रष्टाचार का अध्ययन" के रूप में वर्णित एक अध्ययन से प्रकट हुआ प्रतीत होता है। इसे बार-बार दर्शित करने की कोशिश की गई, कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा हाथ में लिया गया उपरोक्त शोध कार्यक्रम, शासन पर एक सामान्य अध्ययन था, मुख्य रूप से नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी के कामकाज के निर्देश में।साथ में यह भी यह स्वीकार किया गया कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के निर्देश भी यह था।

2. यद्यपि, उपरोक्त अध्ययन प्रत्येक राज्य के निर्देश में स्वतंत्र रूप से आयोजित किया गया था, फिर भी प्रासंगिक अध्ययन, जो हस्तगत रिट

याचिका के याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालयके समक्ष लाया है, उसमें दर्ज निष्कर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिनस्थ न्यायपालिका के निर्देश में संबंधित है, और यहीं तक सीमित है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान तालिका संख्या 2.1 की ओर आकर्षित किया: जम्मू और कश्मीर-सार्वजनिक सेवाओं की रैंकिंग, जिसका उद्धरण, जो वर्तमान विवाद के विषय के लिए प्रासंगिक है, यहां दिया गया है:

विभाग	रिश्वत देने का प्रत्यक्ष अनुभव	सेवा की गुणवत्ता ख़राब है	प्रभाव का बिचौलियों का उपयोग करना	धारणा है कि विभाग भ्रष्ट है	भ्रष्टाचार कम करने के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव	धारणा बढ़ी	समग्र सूचकांक मूल्य

आवश्यकता आधारित

न्यायपालिका (अधीनस्थ)	96	81	09	92	88	86	87

ऊपर दर्शित की गई तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिन लोगों से (अपने विचार व्यक्त करने के लिए) कहा गया था, उनके विचारों

के संकलन से यह निष्कर्ष निकला कि जम्मू और कश्मीर राज्य में निचली न्यायपालिका का 92% हिस्सा भ्रष्ट माना जाता था।

3. तालिका 2.2 का निर्देश लेना भी प्रासंगिक है: (रिश्वत देने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या), जिसमें, जम्मू और कश्मीर राज्य में निचली न्यायपालिका के निर्देश में, अध्ययन में निम्नलिखित डेटा/जानकारी शामिल की गई है:

"तालिका संख्या 2.2: रिश्वत देने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या

विभाग	रिश्वत देने वाले परिवारों की संख्या
न्यायपालिका अधीनस्थ	223267

ऊपर दर्शित की गई तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्देश में वास्तविक रिश्वत देने के 2,23,267 मामलों का खुलासा किया गया था।

4. जम्मू और कश्मीर राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्देश में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन, जम्मू और कश्मीर की न्यायालय ने 4.5.2006 को पांच व्यक्तियों/पक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की,जिनका विवरण यहां नीचे दर्शाया गया है:

1. पी.एन. राज़दान, Op.Ed के लेखक।

पेज- जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार- यहां, वहां और हर जगह- I और II, ग्रेटर कश्मीर में।

2. फ़ैयाज़ अहमद कालू, संपादक मुद्रक एवं प्रकाशक, ग्रेटर कश्मीर 14/बी सनत नगर, श्रीनगर/6 प्रताप पार्क, रेजीडेंसी रोड।

3. ज़हीर-उद-इन- कार्यकारी संपादक ग्रेटर कश्मीर।

4. मीडिया अध्ययन केंद्र अपने निदेशक/सचिव के माध्यम से नई दिल्ली केयर आफ ग्रेटर कश्मीर।

5. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी केयर आफ ग्रेटर कश्मीर के माध्यम से (अप्रार्थी/प्रत्यथिगण)

इसलिए यह स्पष्ट है कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (याचिकाकर्ता संख्या 2, इस न्यायालय के समक्ष) को क्रम संख्या 4 पर नोटिस जारी किया गया था, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (याचिकाकर्ता संख्या 1, यहां) को क्रम संख्या 5 पर नोटिस जारी किया गया था।

5. 4 मई, 2006 के आदेश का विषय भी यहां नीचे पुन: उध्दरित किया गया है:

"आदेश

4 मई 06

"जबकि ग्रेटर कश्मीर, दैनिक समाचार पत्र, अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मुद्रित और प्रकाशित, जैसा कि अप्रार्थी संख्या नंबर 3 द्वारा संपादित किया गया है, ने पेज 7 पर ऑप-एड में एक

लेख प्रकाशित किया है 'जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार- यहां, वहां और हर जगह -' 3 और 4 मई, 2006 के पेपर में अप्रार्थी संख्या 4 और 5 के कुछ संदर्भों के आधार पर, I और II को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिकृत किया गया है।

जबकि लेख का उपशीर्षक बोल्ड फ्रंट में दर्शाया गया है। 'अधीनस्थ न्यायपालिका ' और आगे कॉलम 2, पंक्ति 45 और कॉलम 3 पंक्ति 8 में- जिसमें लेखक का उल्लेख है, "कश्मीर को सबसे भ्रष्ट, 'अधीनस्थ न्यायपालिका (86%) के रूप में देखा जाता है और इसे 'सरकार चूषक" कहा जाता है। 4 मई 06 को प्रकाशित- लेख भाग II में भी- कॉलम 1 और 2 की अंतिम पंक्ति (कॉलम 1) और कॉलम 2 में पहली सात पंक्तियाँ जिन्हें यहाँ नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है। "इकाई या विभाग का एक मजबूत और ईमानदार प्रमुख, जो जनता के प्रति आसानी से उत्तरदायी है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की शक्ति रखता है और राजनीतिक हस्तक्षेप रखता है, परिणाम देना सुनिश्चित करता है।"

जबकि इस तरह का प्रकाशन में अपमानजनक प्रकृति के है, जहां न्यायपालिका के प्रति इस तरह का व्यापक निर्देश सामान्य और अधीनस्थ

न्यायपालिका का है, जैसा कि लेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे न केवल न्याय प्रशासन की पूरी प्रणाली बदनाम होती है, बल्कि लोक सेवकों (अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्य) की भी बदनामी होती है जो न्याय प्रशासन के संबंध में कार्यरत हैं और इस प्रकार पूरी तरह से न्यायपालिका की छवि को कम कर रहे हैं और अदालतों (विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायलय) के अधिकार को कम करके न्यायपालिका की छवि को बदनाम करने और उसे कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं।) और आम जनता के विश्वास को डिगाना और न्याय की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

जबकि इस तरह की सामान्य टिप्पणियाँ अधीनस्थ न्यायपालिका के आचरण और यहां तक कि उनके प्रशासनिक प्रमुखों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जैसा कि भाग II में दिया गया है, जिससे समग्र रूप से विभाग की कार्यप्रणाली की ईमानदारी के बारे में संदेह पैदा होता है।

जबकि इस न्यायालय की राय में, इस अपमानजनक बयान ने न केवल न्यायपालिका की छवि को धुमील किया है और यह न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है और उत्तरदाताओं की ओर से संवेदनहीन और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है।

इसलिए इस कारण बताओ नोटिस के आधार पर आपको इस नोटिस के जारी होने से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने

के लिए कहा जाता है कि क्यों न आपके खिलाफ विधि के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाए।

आज 4 मई, 06 को मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(विशेष महत्व दिया गया)

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दिनांक 4.5.2006 के आदेश का अवलोकन करने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि यह 'कारण बताओ नोटिस' की प्रकृति में है, जिसमें नोटिस प्राप्त करने वालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमारे विचार से यह स्थिति सवीकार करने योग्य है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि दिनांक 4.5.2006 के आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 और/या धारा 2/6 सहपठित 499, 500/501 रणबीर दंड संहिता प्रावधानों के तहत पारित किया गया। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हम मौजूदा विवाद पर निर्णय देते समय प्रतिद्वंद्वी अधिवक्ताओ के तर्कों की जांच करेंगे।

7. इसके बाद (4 मई, 2006 को उपरोक्त दर्शित किये गए नोटिस के जारी होने के बाद), याचिकाकर्ताओं की ओर से यह ध्यान में लाया गया कि दिनांक 16.2.2006 और 1.7.2006 को भी इसी उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किए गए थे। दिनांक 1.07.06 के नोटिस में स्पष्ट रूप से

कहा गया है, "...अब फिर से आपकोसुनवाई कि अगली दिनांक या उससे पहले उपस्थित होने के लिए या आपके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है कि क्यों न ऊपर उल्लेखित संज्ञान के आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं (या अन्य, जिन्हें उपरोक्त नोटिस जारी किए गए थे) की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं चाही गई थी।

8. हस्तगत रिट याचिका के अभिवचनो विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 6 में, स्वीकार किया गया है कि, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (-याचिकाकर्ता संख्या 1) को 7.7.2006 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (-याचिकाकर्ता संख्या-2) को दिनांक 16.06.2006 कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (-याचिकाकर्ता संख्या 2) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्लास-1, कंगन, जम्मू और कश्मीर को 23.6.2006 को निम्नलिखित प्रतिक्रिया संबोधित की गई थी। वही नीचे दर्शाया गया है:

“अनुसंधान गृह

साकेत सामुदायिक केंद्र

नई दिल्ली-110017

23 जून 2006

सेवा में

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

कंगन, जम्मू और कश्मीर

निर्देश: आपका नोटिस दिनांक 16/06/2006, क्रमांक 101/एमके न्यायालय की अवमानना अधिनियम- 1997, धारा 2/6 सहपठित धारा 499, 500/501 आरपीसी।

मान्यवर

हालाँकि 16 जून 2006 के आदेश में उल्लेख किया गया है कि "शिकायत की एक प्रति संलग्न है", परन्तु शिकायत की कोई प्रति संलग्न नहीं की गई है। इसके बजाय, कारण बताओ नोटिस जारी करने और प्रकरण को 19 मई 2006 को पोस्ट करने का निर्देश देने वाले 4 मई, 2006 के आदेश की एक प्रति संलग्न की गई है। 4 मई 2006 का आदेश आज तक हमें प्रदत नहीं किया गया है। पत्र की एक प्रति आदेश दिनांक 16 जून 2006 के साथ प्राप्त हुई है। इसलिए, हमारे पास 4 मई 2006 के नोटिस का जवाब देने का कोई अवसर नहीं है। इस पत्र को 4 मई 2006. को जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस के जवाब के रूप में माना जा सकता है।

शिकायत की प्रति और श्री एफ.एन.राजदान द्वारा ग्रेटर कश्मीर में प्रकाशित जम्मू एवं कश्मीर में भ्रष्टाचार -यहाँ, वहाँ और हर जगह- । और

II शीर्षक वाले लेख की प्रति को बिना उपलब्ध करवाये हमारे लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब देना या इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग-प्रथम, कंगन के माननीय न्यायालय की सहायता करना संभव नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज़, जो अत्यंत आवश्यक हैं, हमें उपलब्ध कराए जाएं। उक्त लेख, जो शिकायत का आधार है, को देखने के बाद ही हम सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में कथित तौर पर दिए गए निर्देश को स्पष्ट कर पाएंगे।

इस समय हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम उक्त लेख के पक्षकार नहीं हैं और उक्त लेख के लेखन या प्रकाशन में हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेख के लेखक या उक्त लेख के प्रकाशन से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेख के लेखक या प्रकाशक या संबंधित समाचार पत्र के संपादक से हमारा कोई संबंध नहीं है।

फिर भी, हम बताना चाहेंगे कि सीएमएस पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं/उपयोगिताओं की सेवाओ में आम नागरिकों से जुड़े भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर रहा है। इस अभ्यास अध्ययन में शामिल विषयों पर प्रख्यात विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है।उधाहरण के लिये विशेष रूप से, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य

न्यायाधीश), श्री प्रशांत भूषण और ऐसे अन्य उत्कृष्ट राष्ट्रीय व्यक्तित्वों से लेखन की प्रक्रिया में किसी न किसी बिंदु पर परामर्श लिया गया है।

वे सभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा कुछ महीने पहले प्रकाशित सर्वेक्षण निष्कर्षों और रिपोर्टों से परिचित हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और इसके अध्यक्ष एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी के सहयोग से सीएमएस द्वारा आयोजित 2005 के भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण में जम्मू-कश्मीर को शामिल किया गया था। जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन सतर्कता आयुक्त (श्री राधाविनोद राजू, आईपीएस) ने चर्चा के लिए नई दिल्ली में सीएमएस का दौरा किया और उन्हें सर्वेक्षण के संचालन से पहले, जम्मू-कश्मीर में सर्वेक्षण के दौरान और रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद इस निर्देश में जानकारी थी।

उक्त अध्ययन में भारत के 19 अन्य राज्यों को शामिल किया गया है। इस संबंध में अग्रणी कार्य के लिए सीएमएस की सराहना की गई है और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोगों ने अध्ययन के लिए हमें धन्यवाद दिया था। अध्ययन के निष्कर्षों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके अध्यक्ष एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी ने इस आशा के साथ व्यक्तिगत रुचि ली कि अधिक विश्वसनीय फ़ील्ड डेटा के साथ राष्ट्र के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में गंभीरता प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, भारत के सचेत नागरिक के रूप में, हम देश में न्यायपालिका की स्थिति और भूमिका को बनाए रखने में उतनी ही ईमानदारी से संबंध और रुचि रखते हैं। वास्तव में, सीएमएस के अध्यक्ष ने पिछले दशक में भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक के साथ मिलकर काम किया था। हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक थे, जबकि वे क्रमशः संचार मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल के अध्यक्ष भी थे।

हमारी ओर से न्यायपालिका के अधिकार को लांछित करने या कम करने का कभी कोई आशय नहीं था, न्याय के उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना या किसी भी तरह से न्याय प्रशासन में बाधा डालना तो बहुत दूर की बात थी।

हम प्रार्थना करते हैं कि ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 1 जुलाई, 2016 को उपस्थिति का निर्देश देने वाला आदेश वापस लिया जाए और हमारे विरुद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया जाए।

धन्यवाद

भवदीय

मीडिया अध्ययन केंद्र के लिए

(विशेष महत्व दिया गया)

9. दिनांक 7.7.2016 को एक अलग जवाब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (याचिकाकर्ता नंबर 1) की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन को भी संबोधित की गई थी। चूँकि प्रतिक्रिया कई पृष्ठों में है, संक्षिप्तता के लिए, हम यहाँ उसका केवल एक प्रासंगिक भाग ही उल्लेखित कर रहे है।

> "हालांकि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हम निम्नलिखित निवेदन करना चाहेंगे:
>
> 1. हम जानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है। वे अधिक से अधिक उच्च न्यायालय को निर्देश दे सकते हैं और तब उच्च न्यायालय मामले पर निर्णय ले सकता है।
>
> 2. हम मानते हैं कि आपका नोटिस केवल आपको यह निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए है कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना है या नहीं।
>
> 3. हम मानते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया उपरोक्त को सक्षम करने के लिए है न कि इस स्तर पर सीधे अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए।

4. अब हम इस नोटिस का जवाब संलग्न कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ अवमानना, मानहानि और मानहानि के आरोप में कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए।"

(विशेष महत्व दिया गया)

10. ऊपर दिए गए जवाबों के उपरोक्त उद्धरणों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ताओं ने कारण बताओ कार्यवाही शुरू करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह ध्यान देना जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन को सूचित किया कि हालांकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय का निर्देश देना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मजिस्ट्रेट न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः कार्यवाही प्रारम्भ करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने उत्तर में उपरोक्त तथ्य दर्ज करने के अलावा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला, कि उसने समाचार पत्र का वह लेख नहीं देखा था, जो कारण बताओ का आधार था। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का समाचार पत्र-ग्रेटर कश्मीर के लेखक/प्रकाशक/संपादक के साथ कोई संबंध नहीं था। उत्तर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यों/गतिविधियों और साख के बारे में भी बताया गया। जो भी हो, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया में, उक्त

पत्र के निर्देश में, साथ ही उसकी सामग्री में, स्वीकार किया है कि जम्मू एवं कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1997 और/या रणबीर दंड संहिता की धारा 2(द) सहपठित धारा 499, 500/501 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

11. ऐसा लगता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन की न्यायालय से प्राप्त नोटिस का जवाब देने के बाद (ऊपर सधर्भित पत्राचार के माध्यम से) याचिकाकर्ता संतुष्ट थे कि उनसे कोई और प्रतिक्रिया नहीं मांगी जावेगी। और इसलिए, दिनांक 16.6.2006 और 1.7.2006 के आदेशों के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन के समक्ष उपस्थित होने के आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की गैर-उपस्थिति के परिणामस्वरूप, दिनांक 24.8.2006 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश को नीचे पुन: उध्दरित किया गया है:

> “जबकि उपरोक्त एक रोबकर शीर्षक वाला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और उक्त अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे में आपसे उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे 27.9.06 को इस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए आदेशित किया जाता है। यदि उक्त व्यक्ति

15,000/ रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करता है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।"

(विशेष महत्व दिया गया)

उपरोक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि उत्तरदाताओं को न्यायालय में सम्मन के माध्यम से बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे, और इसलिए, उनकी उपस्थिति जमानती वारंट के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही थी।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आदेश दिनांक 24.8.2006 को चुनौती देते हुवे में जोरदार ढंग से तर्क दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन ने, उच्च न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है। यह तर्क दिया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन के पास अवमानना कार्यवाही के तहत याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था। यह तर्क दिया गया कि उपर्युक्त उल्लेखित आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से परे था। इस बात पर जोर दिया गया कि जब मामला इस न्यायालय के समक्ष पहली बार, 20.9.2006 को, सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय ने अगले आदेश तक, दिनांक 24.8.2006 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। यह स्पष्ट रूप

से कहा गया था, कि यह न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अवमानना कार्यवाही के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग के बारे में स्पष्ट रूप से सचेत रहा होगा, इसी कारण अपने मोशन बेंच आदेश दिनांक 20.9.2006 में, इस न्यायालय ने न केवल गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन (अध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और निदेशक, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के विरुद्ध जारी),पर रोक लगा दी वरन मामले में आगे की कार्यवाही (संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित) पर भी रोक लगा दी।

13. उपरोक्त व्यक्त स्थिति की निरंतरता में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि जम्मू और कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 के तहत, अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र केवल उच्च न्यायालय के पास निहित है। इसके लिए, इसकी धारा 10 का निर्देश दिया गया है, जिसे नीचे पुनः उध्दरत किया गया है:

> “10. अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा दंडित करने की शक्ति:- उच्च न्यायालय के पास अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में उसी प्रक्रिया और अभ्यास के अनुसार समान क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार होंगे और उनका प्रयोग किया जाएगा। अवमानना के संबंध में ही:

परन्तुक कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में की गई कथित अवमानना का संज्ञान नहीं लेगा, जहां ऐसी अवमानना रणबीर दंड संहिता, संवत 1989 के तहत दंडनीय अपराध है।" (विशेष महत्व दिया गया)

उपरोक्त धारा 10 के प्रावधान के आधार पर, यह तर्क दिया गया था, कि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय कि अवमानना का आरोप लगाया गया था, तब भी केवल क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के पास अवमानना कार्यवाही सुरु करने का अधिकार क्षेत्र था, न कि अधीनस्थ न्यायालय का (जिसके खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया गया था)।

14. इसके अलावा, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि आपराधिक अवमानना का संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय के इन्सरास पर लिया जा सकता था,परन्तु यह तर्क दिया गया कि फिर भी केवल उच्च न्यायालय के पास मामले में कार्रवाई शुरू करने का अधिकार था। इसके लिए, 1997 अधिनियम की धारा 15 का निर्देश दिया गया था, जिसे नीचे पुन: उध्दरत किया गया है:

“15. अन्य मामलों में आपराधिक अवमानना का संज्ञान:-

(1) आपराधिक अवमानना के मामले में, धारा 14 में निर्दिष्ट अवमानना के अलावा, उच्च न्यायालय स्वतः या

निम्नलिखित द्वारा किए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है -

(ए) महाधिवक्ता; या

(बी) कोई अन्य व्यक्ति, महाधिवक्ता की लिखित सहमति से।

(2) अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आपराधिक अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर या महाधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है।

(3) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या निर्देश में उस अवमानना को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए आरोपित व्यक्ति कथित रूप से दोषी है।

"स्पष्टीकरण.- इस खंड में, अभिव्यक्त "महाधिवक्ता" का अर्थ राज्य का महाधिवक्ता है।" (विशेष महत्व दिया गया)

ऊपर उल्लेखित कि गई धारा 15 के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि केवल वह अधीनस्थ न्यायालय, जिसके खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप लगाया गया है, उसी पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय को निर्देश दे सकता है। धारा 15 की उप-धारा (2) पर विश्वास

करते हुए, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि यह केवल वह न्यायालय है, जिसकी अवमानना की गई है, और जिसे इसका आंतरिक ज्ञान था और वह इस तरह का निर्देश देने के लिए अधिकृत था, न कि कोई और न्यायालय।

15. यह तर्क दिया गया कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट का उद्धरण, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित करनी चाही गई थी, एक अध्ययन पर आधारित सामान्य रिपोर्ट थी। और यह कि, रिपोर्ट किसी विशेष न्यायालय पर लक्षित नहीं था, और इस तरह, यह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी सूरत में यह नही था कि वह अधिनियम 1997 कि धारा 15 के अर्थो में निर्देश करता।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंगन को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के बाद विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। इस संबंध में यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिस पर उनकी प्रतिक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए था और आगे की कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अखबार की रिपोर्टिंग लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

17. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के दिए गये तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हमने जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है, जिन्होंने सामान्य तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन द्वारा पारित विभिन्न आदेश मामले का समर्थन किया है।

18. हम सर्वप्रथम 1997 के अधिनियम की धारा 15 के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में से एक पर विचार करना चाहेंगे। यह तर्क दिया गया कि केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा ही निर्देश दिया जा सकता है, जिसकी कथित रूप से अवमानना की गई है, न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा। और वह, केवल उक्त विशेष न्यायालय, अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश दे सकती है। कम से कमहस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे विचार में कारण से उपरोक्त विवाद को न्यायालय के समक्ष लाया गया है, कि अधीनस्थ न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश देना अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, जहां कि सामान्य आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, समाचार पत्र- ग्रेटर कश्मीर में लेख का प्रकाशन, जिसमें केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, किसी भी कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (याचिकाकर्ता संख्या 2) के

संकलन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (याचिकाकर्ता संख्या 1) द्वारा संकलित संकलन के प्रकाशन के आधार पर इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका के 92% को भ्रष्ट माना जाता था और वहां 2,23,267 मामलों के वास्तविक आंकड़े थे, जहां वास्तव में रिश्वत दी गई थी। लेकिन किसी विशिष्ट न्यायाधीश या न्यायालय पर लक्षित कोई आरोप नहीं थे। केवल इसलिए कि उपरोक्त आरोप किसी विशेष न्यायालय पर लक्षित नहीं थे, 1997 अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तर्क को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि 1997 अधिनियम की धारा 15(2) में प्रयोग किया गया शब्द "अधीनस्थ न्यायालय" एक ऐसी स्थिति पर विचार कर सकता है, जहां कथित अवमाननापूर्ण कार्रवाई का उद्देश्य एक से अधिक न्यायालयों, या बड़ी संख्या में न्यायालयों को लक्षित है। उस स्थिति में, हमारे विचार में, ऐसी न्यायालयों में से कोई भी, जम्मू और कश्मीर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत, उच्च न्यायालय का निर्देश दे सकती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें माना जा सकता है कि निष्कर्ष निकाला है, कि जहां अवमाननापूर्ण कार्रवाई सामान्य प्रकृति की है, और विशिष्ट न्यायाधीशों या न्यायालयों को लक्षित नहीं है, ऐसे न्यायाधीशों या न्यायालयों में से कोई भी, जो मानता है कि इसका उद्देश्य उसके (या उसके) लिए है, इसके दायरे में होगा तथा अधिकार क्षेत्र वाले

उच्च न्यायालय को इसका निर्देश देने का अधिकार होगा। और उसके बाद, क्या संज्ञान लेने और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है, यह उच्च न्यायालय के दायरे में ही आएगा।

19. हालाँकि, हम यह स्वीकार करने में संतुष्ट हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंगन के पास दिनांक 24.8.2006 के आक्षेपित आदेश को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था, जिसके तहत, उसने याचिकाकर्ताओं (अन्य के साथ) की गिरफ्तारी के माध्यम से उपस्थिति को सुनिश्चित करने पर विचार किया। हमारा यह भी विचार है कि मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं ने माना था कि 4.5.2006 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही त्रुटिपूर्ण थी। और तदनुसार, उन्होंने लिखित तर्कों व निवेदन में, यह स्वीकार किया कि "... हम मानते हैं कि आपका नोटिस केवल आपको यह निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए है कि क्या अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश दिया जाए... हम मानते हैं कि हमारी जवाब उपरोक्त हेतु आपको सक्षम करेंगा और इस स्तर पर आप सीधे अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ नही करेंगे। याचिकाकर्ताओं से उपरोक्त जवाब प्राप्त करने के बाद, और याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं की न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले पर विधि के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए था। और यदि यह न्यायालय का विचार था कि मामले को आगे ले जाने की आवश्यकता है,तब या तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1997

के तहत और/या रणबीर दंड संहिता की धारा 499, 500/501 सहपठित धारा 2/6 के तहत, न्यायालय को ऐसा करना चाहिए था।

20. उपरोक्त के मद्देनजर, हस्तगत याचिका का निस्तारण करते हुए, हम वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन (न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कंगन के न्यायालय का प्रभार संभालने वाले न्यायिक अधिकारी) को मूल कारण बताओ नोटिस दिनांक 4.5.2006 के अनुरूप में आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से) के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। यदि याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो वह विधि के अनुरूप ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, जो वह उचित समझे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता इससे व्यथित हैं तो वे उसे चुनोती देने के लिए स्वतंत्र होंगे। आदेश दिनांक 24.8.2006 को निरस्त कर दिया जाता है।

21. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 199-बी पर भी विश्वास जाहिर किया, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, तथा यह तर्क दिया कि, रणबीर दंड संहिता की धारा 499, 500/501 के सहपठित धारा 2/6 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को विकल्प प्राप्त

नहीं है। हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को रिकॉर्ड करते हैं, और यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रणबीर दंड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही आगे बढ़ना चाहते है, तो न्यायालय धारा 199-बी के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर उचित रूप से विचार करेगा।

22. आदेश लिखवाए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमें सूचित किया कि एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी, जिन्हें दिनांक 16.6.2006 और 1.7.2006 को नोटिस जारी किए गए थे, का निधन हो गया है, और इस प्रकार, उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है जिसे समाप्त कि जाये । हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के दिए गए तर्क में बल पाते हैं। एडमिरल आर.एच. ताहिलियानी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही समाप्त/एवेट मानी जाएगी।

23. रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है। मुख्य याचिका के निस्तारण के परिणामस्वरूप, सभी लंबित आवेदनों को भी निश्तारित समझी जावे।

अपील निस्तारित

यह अनवुाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ सूर्य प्रकाश पारीक (जिला न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा किया गया है।

यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारित उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।